THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT) WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY) (SMT. KRISHNA SAHI): (a) Since manufacture of carts has been delicensed, approval of Government is not required for the same.

(b) M/s. Hindustan Motors have been granted approval for setting up a joint venture with M/s. General Motors of U.S.A., for the manufacture of cars. Recently Premier Automobiles Ltd. have submitted a proposal for setting up a joint venture for the manufatcue of cars in collaboration with M/s. Peugeot of France.

ग्रामीण उद्योगों का विकास

1964. **श्री गोपाल सिंह जी सोलंकी :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्रामीण उद्योगों के विकास के लिए कम धन आबंटित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) पिछले चार वर्षों के दौरान ग्रामीण उद्योगों के विकास के लिए वर्ष वार कितना धन खर्च किया गया ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग और कृषि तथा ग्रामीण उद्योग) में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) ग्रामीण उद्योगों के विकास हेतु पिछले 4 वर्षों के दौरान खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग को केन्द्र सरकार द्वारा आवंटित की गई धनराशि का विवरण नीचे दिया गया है :–

वर्ष	धनराशि (रु० लाख में)
1989–90	17500
1990–91	18600
1991–92	19300
1992–93	19300

इसके अलावा ग्रामीण उद्योगों के विकासार्थ चालू वर्ष के दौरान खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग को 21000 लाख रुपए की धनराशि का बजट आवंटन किया गया है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में बिजली की कमी

1965. **श्री गोपाल सिंह जी सोलंकी :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र की क्षमता के कम उपभोग का प्रमुख कारण बिजली की कमी है ;

(ख) यदि हां, तो कौन-कौन से उपक्रम बिजली की कमी की समस्या का सामना कर रहे हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री और उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में क्षमता के कम उपयोग के विभिन्न कारण हैं। एक ऐसा कारण बिजली की कमी है और अन्य प्रमुख कारण हैं :—क्रय आदेश की खराब स्थिति, कच्चे माल की कमी/अनुपलब्धता, कार्यशील पूंजी/नकदी की समस्यायें, संयंत्र

तथा मशीनरी की खराबी तथा कम उत्पादकता। उपलब्ध जानकारी के अनुसार सरकारी क्षेत्र के 19 उपक्रमों में वर्ष 1991–92 के दौरान केवल जिस वर्ष की नवीनतम जानकारी उपलब्ध है, बिजली की कमी के कारण उत्पादन बुरी तरह प्रभावित हुआ। इन उपक्रमों के नाम विवरण (नीचे देखिए) में दिये गये हैं। इस संबंध में किये गये उपचारी उपाय हैं–निजी विद्युत संयंत्रों की स्थापना करना, प्रौद्योगिकी का आधुनिकीकरण तथा उसे समुन्नत बनाना, ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा के वैकल्पिक साधनों का उपयोग करना आदि।

विवरण

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के नाम

1. भारतीय सीमेंट निगम लि0
2. कोल इंडिया लि0
3. दामोदर सीमेंट एण्ड स्लैग लि0
4. भारतीय उर्वरक निगम लि0
5. फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स (त्रावणकोर) लि०
6. भारी इंजीनियरी निगम लि0
7. हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपो0 लि0
8. हिन्दुस्तान इंसैक्टीसाइड्स लि0
9. हिन्दुस्तान पेपर कारपो0 लि0
10. हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपो0 लि0
11. हिन्दुस्तान जिंक लि0
12. कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी लि0
13. मद्रास फर्टिलाइजर्स लि0
14. मिश्रधातु निगम लि0
15. नागालैण्ड पल्प एण्ड पेपर कंपनी लि0
16. तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग
17. राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि0
18. टेनरी एण्ड फुटवियर कारपो0 आफ इंडिया लि0
19. विश्वेश्वरैया आयरन एण्ड स्टील लि0

Establishment of salt manufacturing units near Kandla

1966. SHRI MENTAY PADMANABHAM: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether the Salt Commission has submitted a report advocating objections to the establishment of a large salt manufacturing unit near Kandla by Messrs Cargill a Us multi-national;.

(b) what are the details of the objections raised by the Salt Commissioner to this proposal;

(c) what action has been taken in this regard;

(d) whether it is a fact that Ministry as soft-pedalled the report of the Salt Commissioner;

(e) if so, the reasons therefor;

(f) whether the report has categorically stated that the surplus of salt already exceeds lakhs of tons per annum;, and

(g) whether any proposal has been put to Cargill' by Government to produce salt and them sell it, rather than clear the existing proposal?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT) WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY) (SMT. KRISHNA SAHI): (a) to (f) A letter of permission has been issued to M/s. Cargil South-East Asia Ltd. Singapore in August, 1992 to set up a 100 per cent EOU in Kutch Distt, of Gujarat for manufacture of 10 lakhs tonnes of solar salt per annum. The party had later on approached Kandla Port Trust for allotment of 15,000 acres of land, which was not approved by the Kandla Port Trust Board. The Government has not received any report whatsoever from the Salt Commissioner in this regard.

(8) No, Sir.